

>

Title: Regarding early payment of dues to sugarcane farmers of Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे देश में गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में गन्ना उत्पादन होता है, जिसमें 28 जिले ऐसे हैं जिनकी पहचान ही गन्ना उत्पादन के लिए है। महोदय, मेरठ और आसपास के जिलों में पिछले कुछ महीनों से गन्ना किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गन्ना किसानों को कुछ चीनी मिलों द्वारा अपनी फसल का पूर्ण भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार सितम्बर, 2019 तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के चीनी मिलों पर 6,400 करोड़ रुपये बकाया हैं। प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद पहले के मुकाबले बकाया भुगतान की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होने के बावजूद अभी भी मेरठ एवं हापुड़ में चीनी मिलों के पास किसानों के लगभग 700 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इस कारण गन्ना किसान अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही चीनी मिलों से गन्ना किसानों को समय पर गन्ने की पर्ची न मिलने के कारण किसान मजबूरन अपनी फसल गन्ना बिचौलियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह गन्ना किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए यह सुनिश्चित करें कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय खाद्य निगम को भी यह निर्देश दिया जाए कि वह अपने चीनी भण्डारण में इजाफा करे, ताकि किसानों को उनके बकाये का शीघ्र भुगतान हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रेखा वर्मा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री मलूक नागर को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।